

[ 2015 ] 4 एस. सी. आर 497

विक्रम सीमेंट और एक अन्य.

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य.

( 2003 की सिविल अपील No. 8192)

17 मार्च, 2015

मध्य प्रदेश स्थायी क्षेत्र में मल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 - प्रवेश कर-की दर-एक सीमित अवधि के लिए अधिसूचना दिनांक 4.5.1999 द्वारा घटाया गया i.e. 1.5.1997 से 30.9.1997 तक-तथापि, अधिसूचना के लिए स्पष्टीकरण जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि कर का भुगतान पहले ही उस अवधि के लिए उच्चतर दर पर किया गया था, तो निर्धारिती को वापस नहीं किया जाएगा - आयोजित किया गया: अधिसूचना का स्पष्टीकरण भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह करदाताओं की दो श्रेणियों यानी i.e. एक जिसने पहले ही कर का भुगतान कर दिया है और दूसरा जिसने अधिसूचना जारी होने के बाद कर का भुगतान

किया है-उन दो वर्गों के निर्माण के पीछे कोई आधार या तर्क नहीं है जिनका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई कारण संबंध होगा - यह स्पष्टीकरण भी कला का उल्लंघन करता है। संविधान की धारा 265-अतः अधिसूचना का स्पष्टीकरण असंवैधानिक है - अधिसूचना संख्या A- 3-80-98-ST-V (49) दिनांक 4.5.1999- अधिसूचना का स्पष्टीकरण-अधिसूचना दिनांक 5. 7. 1999- भारत का संविधान, 1950- कला 14 और 265।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने कहा:

1. दिनांक 4.5.1999 की अधिसूचना से या उस मामले के लिए दिनांक 5.7.1999 की अधिसूचना से संलग्न स्पष्टीकरण, जिसमें कहा गया है कि राशि किसी भी मामले में इस आधार पर वापस नहीं की जाएगी कि विक्रेता ने उच्च दर पर कर दाखिल किया था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों की तरह उच्च दर पर कर का भुगतान करने वालों के प्रति पक्षपातपूर्ण भेदभाव होता है, जब उन व्यक्तियों की उस श्रेणी की तुलना में जो चूककर्ता थे और जिन्हें अब प्रासंगिक अवधि के लिए 1% की दर से कर का भुगतान करने की अनुमति दी गई है। इसका परिणाम यह

है कि यह करदाताओं की दो श्रेणियों का निर्माण करता है, जिन्हें अलग-अलग दरों पर कर का भुगतान करना पड़ता है, भले ही वे समान रूप से स्थित हों। इन दो वर्गों के निर्माण का कोई आधार नहीं है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई कारण संबंध होना चाहिए। स्पष्टीकरण प्रकृति में अत्यधिक भेदभावपूर्ण है। [पैरा 1 और 10] (503- F-H; 504-A-C; 508-D)

एस. नकारा और ओआरएस। v. भारत संघ 1983 (2) SCR 1 E 165: (1983) 1 SCC 305; Re. : विशेष न्यायालय विधेयक, 1978.1979 (2) एस. सी. आर. 476: (1979) 1 धारा 380; ई. पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) 2 एस. सी. आर. 348-पर निर्भर था।

2. दिनांक 4.5.1999 की टाइल अधिसूचना का प्रभाव यह होगा कि कच्चा माल लाने वाला कोई भी व्यक्ति, अर्थात्। मध्य प्रदेश राज्य के भीतर कोयला, जिप्सम और बॉक्साइट केवल 1% की दर से प्रवेश कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। एक बार इस पहलू को ध्यान में रखने के बाद, इसका कानूनी प्रभाव यह होना चाहिए कि अपीलार्थियों

सहित सभी व्यक्ति, जिन्होंने पहले ही कर का भुगतान कर दिया था, उन्हें भुगतान करना था। केवल 1% की दर से कर।

इसलिए, यदि उन्होंने अधिक दर पर कर का भुगतान किया था, तो वे भुगतान की गई कर की अतिरिक्त राशि की वापसी के हकदार थे। इस प्रकार, चूंकि देय प्रवेश कर केवल 1% की दर से था, इसलिए किसी भी व्यक्ति को उच्च दर पर भुगतान करने के लिए कहना संविधान के अनुच्छेद 265 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होगा। संविधान के अनुच्छेद 265 को दिए गए संदर्भ में अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। (Paras 12, 13) [508-ई-जी ~ 509ए-सी]

3. इस धारणा पर कि अधिसूचना में इस स्पष्टीकरण को जोड़ते समय, सरकार ने अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत को ध्यान में रखा था, स्पष्टीकरण को जोड़ने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष विक्रेता है

वास्तव में धनवापसी का हकदार है या नहीं, सरकार धनवापसी के लिए उसके आवेदन पर विचार करते समय

अन्यायपूर्ण संवर्धन के मुद्दे पर जा सकती है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह नहीं माना जा सकता है कि इन विक्रेताओं द्वारा खरीदारों पर सकारात्मक रूप से बोझ डाला गया था और इसलिए, वे धनवापसी के हकदार नहीं हैं। अतः दिनांक 4.5.1999 और 5.7.1999 की अधिसूचनाओं में आक्षेपित स्पष्टीकरण असंवैधानिक हैं।

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 2003 का 8192.

जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 11.09.2002 के निर्णय और आदेश से रिट याचिका सं. 2000 का 6459।

अपीलार्थी की ओर से नीरज शर्मा।

उत्तरदाताओं की ओर से अरविंद वर्मा, सी. डी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

1. डा. ए. के. सीकरी, जे.- इस अपील पर निर्णय लेने के लिए जिन न्यूनतम तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, उन्हें संक्षेप में नीचे दिया गया है.
2. अपीलार्थी 1 और 2 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की इकाइयाँ हैं, जो सीमेंट का निर्माण और बिक्री करती हैं। इसके लिए कोयले, जिप्सम और बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की आवश्यकता होती है। उपरोक्त कच्चे माल पर, अपीलार्थी M.P. के तहत मध्य प्रदेश राज्य के क्षेत्र में इन वस्तुओं के प्रवेश के लिए प्रवेश कर का भुगतान कर रहे थे। स्थायी क्षेत्र में मल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (इसके बाद इसे "प्रवेश कर अधिनियम" कहा जाता है) वर्ष 1997 में, अधिनियम के तहत देय कच्चे माल की उपरोक्त वस्तुओं पर प्रवेश कर निम्नलिखित दरों पर था:

कोयला-2.5%

जिप्सम-2%

बॉक्साइट-10%

वर्ष 1999 में, प्रत्यर्थी 1 राज्य ने अधिसूचना सं. ए-380-98-एसटी-वी (49) दिनांक 4-5-1999। इस अधिसूचना द्वारा इसने प्रवेश कर को केवल 1% की दर से देय करके प्रवेश कर, अर्थात्

कोयला, जिप्सम और बॉक्साइट की दर को कम कर दिया। यह अधिसूचना 1-5-1997 से 30-9-1997 तक सीमित अवधि के लिए लागू रही। 1-5-1997 से पहले और 30-9-1997 के बाद प्रवेश कर की दर समान रही, अर्थात् कोयला, जिप्सम और बॉक्साइट के लिए क्रमशः 2.5%, 2% और 10%.

3. हम यहां उपर्युक्त अवधि के बारे में चिंतित हैं जब देय प्रवेश कर केवल 1% था। हालांकि, प्रवेश कर को 1% तक कम करते हुए, उसी अधिसूचना में एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया था जिसमें कहा गया था कि डीलर द्वारा पहले से ही उच्च दर पर भुगतान की गई राशि वापस नहीं की जाएगी। यह स्पष्टीकरण निम्नलिखित शब्दों में दिया गया है:

स्पष्टीकरण-राशि किसी भी मामले में इस आधार पर वापस नहीं की जाएगी कि विक्रेता ने उच्च दर पर कर का भुगतान किया था।

चूंकि अधिसूचना केवल मई 1999 में जारी की गई थी और यह पिछली अवधि i.e से संबंधित थी। 1-5-1997 से 30-9-1997 तक और राज्य में माल के प्रवेश के बिंदु पर प्रवेश कर देय है,

जब और जब अपीलार्थी मध्य प्रदेश राज्य में उपर्युक्त कच्चा माल ला रहे थे, तो वे प्रवेश कर का भुगतान कर रहे थे। 1-5-1997 से 30-9-1997 की अवधि के दौरान, उन्होंने उस समय प्रचलित दर पर प्रवेश कर का भुगतान किया था, हालांकि 4-5-1999 की अधिसूचना द्वारा 1% तक कम कर दिया गया था। इस तरह से, अपीलार्थियों के अनुसार, हालांकि उन्होंने उच्च दर पर प्रवेश कर का भुगतान किया था, जिसे अब उपरोक्त अधिसूचना द्वारा घटाकर 1% कर दिया गया था, वे भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वापसी प्राप्त करने के हकदार बन गए, लेकिन फिर भी उपरोक्त स्पष्टीकरण के कारण उस वापसी से वंचित थे।

4. स्वाभाविक रूप से, उक्त स्पष्टीकरण से व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके स्पष्टीकरण की वैधता को चुनौती दी। चुनौती का नेतृत्व मुख्य रूप से दो पहलुओं पर किया गया था:
- (i) प्रथम दृष्टांत में, यह अभिवचन किया गया था कि यह स्पष्टीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारण मनमाना और भेदभावपूर्ण था क्योंकि उक्त स्पष्टीकरण

के कारण जो वर्गीकरण किया गया है, उसका प्रभाव अपीलार्थियों और अन्य लोगों के साथ, जिन्होंने उच्च दर पर कर का भुगतान किया था, उन लोगों से अलग व्यवहार करने का था जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया था और चूक की थी। यह तर्क दिया गया था कि इस तरह का वर्गीकरण किसी भी बोधगम्य अंतर पर आधारित नहीं था और प्राप्त किए जाने वाले किसी भी उद्देश्य के साथ इसका कोई संबंध नहीं था। इस तर्क के समर्थन में उच्च न्यायालय में कई निर्णयों का हवाला दिया गया था।

(ii) दूसरा तर्क यह उठाया गया था कि यह कोयला, जिप्सम और बॉक्साइट के लिए क्रमशः 2.5%, 2% और 10% की उच्च दर पर कर लगाने के बराबर है, हालांकि 4-5-1999 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन अवधि के लिए अंततः निर्धारित दर 1% थी। इसलिए, अधिसूचना में इस तरह का 'स्पष्टीकरण' संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत अवैध था।

5. उच्च न्यायालय ने, हालांकि उपरोक्त तर्कों पर ध्यान दिया, इन तर्कों को उस तरीके से नहीं निपटाया जिसमें ये प्रस्तुतियाँ की गईं और रिट याचिका को दिनांक 11-9-2002 के विवादित

निर्णय [विक्रम सीमेंट बनाम M.P. राज्य] द्वारा खारिज कर दिया। डब्ल्यूपी नं. 2000 का 6459,11-9-2002 (एम. पी.) को केवल इस आधार पर विनिश्चय किया गया कि सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ M.P. में पहले अपनी डिवीजन बेंच द्वारा समान मुद्दे पर विचार किया गया था। [सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ M.P., 2000 SCC ऑनलाइन MP 192: (2001) 1 MPLJ 694] उच्च न्यायालय के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, हम यह भी उल्लेख करेंगे कि उच्च न्यायालय ने इंडियन ऑयल कॉर्प में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का उल्लेख किया है। v. नगर निगम, जालंधर [इंडियन ऑयल कॉर्प। v. नगर निगम, जालंधर, (1993) 1 एस. सी. सी. 333] और उक्त मामले में टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए कि जहां चुंगी शुल्क पहले ही एकत्र किया जा चुका था, वहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पक्ष में किसी भी इक्विटी का रिफंड का दावा करने का कोई सवाल ही नहीं था।

6. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमारे सामने वही दलीलें रखी हैं जो उच्च न्यायालय के समक्ष इस याचिका के साथ प्रस्तुत की गई थीं कि उच्च न्यायालय ने उन

दलीलों पर उचित रूप से विचार भी नहीं किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह अपीलार्थियों के साथ भेदभाव का एक स्पष्ट मामला था, जिन्होंने ईमानदारी से कर का भुगतान किया था और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों को पूरी तरह से आकर्षित करेंगे। दूसरी ओर, राज्य के विद्वत वकील ने अपीलार्थियों के विद्वत वकील की दलीलों का प्रतिवाद करते हुए अपनी दलीलों के समर्थन में विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क का उल्लेख किया।

7. संबंधित मुद्दे पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील को प्रस्तुत करने में बल है। दिनांक 4-5-1999 की अधिसूचना या उस मामले के लिए दिनांक 5-7-1999 की अधिसूचना के साथ संलग्न स्पष्टीकरण, जिसमें कहा गया है कि राशि किसी भी मामले में इस आधार पर वापस नहीं की जाएगी कि विक्रेता ने उच्च दर पर कर दाखिल किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन लोगों के प्रति अपमानजनक भेदभाव होता है जिन्होंने उच्च दर पर कर का भुगतान किया है, जैसे अपीलार्थी, जब उन व्यक्तियों की उस श्रेणी की तुलना में जो चूककर्ता थे और जिन्हें अब

प्रासंगिक अवधि के लिए @1% कर का भुगतान करने की अनुमति दी गई है। इसका परिणाम यह है कि यह करदाताओं की दो श्रेणियों को अलग करता है जिन्हें अलग-अलग दरों पर कर का भुगतान करना पड़ता है, भले ही वे समान रूप से स्थित हों। इन दोनों वर्गों के निर्माण का कोई आधार नहीं है और इसके पीछे कोई तर्क नहीं है जिसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई कारण संबंध हो। यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील से बार-बार किए गए प्रश्न पर, वह किसी भी सामग्री को स्पष्ट नहीं कर सके या रिकॉर्ड पर नहीं दिखा सके कि अधिकारियों को ऐसा स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए क्या प्रेरित किया। इसलिए, यह स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 4-5-1999 की अधिसूचना में संलग्न ऐसे स्पष्टीकरण के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है, सिवाय इसके कि सरकार, उन लोगों से कर एकत्र करने के बाद जिन्होंने उच्च दर पर भुगतान किया था, उसी को वापस करने का इरादा नहीं था। इसे शायद ही स्वीकार किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब इसके परिणामस्वरूप दोनों समूहों के बीच भेदभाव होता है, हालांकि समान रूप से स्थित होता है।

8. संविधान के अनुच्छेद 14 के दायरे और अर्थ पर कानून अब अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है। हम लाभकारी रूप से D.S. का उल्लेख कर सकते हैं। नकारा बनाम भारत संघ [D.S.] नकारा बनाम भारत संघ, (1983) 1 एस. सी. सी. 305:1983 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 145], जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की: (paras 10-11)

"10. संविधान के अनुच्छेद 14 का दायरा, विषय-वस्तु और अर्थ इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में गहन जांच का विषय रहा है। इसलिए, यह केवल उन सभी निर्णयों का पुनर्कथन करने के लिए इस निर्णय की लंबाई को जोड़ना होगा और मेनका गांधी बनाम भारत संघ में इस विषय पर नवीनतम निर्णय का उल्लेख करने के अलावा उस अभ्यास से बचना बेहतर है, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन निकाला जा सकता है: (para 7)

'7. इस लेख में प्रतिपादित महान समानता सिद्धांत की विषय-वस्तु और पहुंच क्या है? इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह संविधान का एक संस्थापक विश्वास है। यह वास्तव में वह स्तंभ है जिस पर हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव सुरक्षित रूप से टिकी हुई है। और,

इसलिए, इसे एक संकीर्ण, पांडित्यपूर्ण या शब्दकोश दृष्टिकोण के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। इसके सर्वव्यापी दायरे और अर्थ को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना इसके सक्रिय परिमाण का उल्लंघन करना होगा। समानता कई पहलुओं और आयामों के साथ एक गतिशील अवधारणा है और इसे पारंपरिक और सैद्धांतिक सीमाओं के भीतर नहीं रखा जा सकता है। ... अनुच्छेद 14 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करता है और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करता है। तर्कसंगतता का सिद्धांत, जो कानूनी रूप से और साथ ही दार्शनिक रूप से, समानता या गैर-मनमानेपन का एक आवश्यक तत्व है, अनुच्छेद 14 में एक सर्वव्यापी सर्वव्यापीता की तरह व्याप्त है।

11. निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हालांकि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को मना करता है, लेकिन यह विधान के उद्देश्य के लिए उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है। तथापि, अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। (i)

कि वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतर पर स्थापित किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों या चीजों को समूह से अलग करता है जो समूह से बाहर हैं; और (ii) कि उस अंतर का उन उद्देश्यों के लिए एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जो विचाराधीन कानून द्वारा प्राप्त किए जाने की मांग की गई है. वर्गीकरण को प्राप्त करने की मांग की गई वस्तुओं के अनुसार अंतर आधार पर स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो निहित है वह यह है कि एक नेक्सस i.e होना चाहिए। वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन कानून के उद्देश्य के बीच कारण संबंध। इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा यह समान रूप से अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 14 न केवल एक ठोस कानून द्वारा बल्कि प्रक्रिया के कानून द्वारा भी भेदभाव की निंदा करता है।

9. पुनः विशेष न्यायालय विधेयक, 1978, में इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रतिष्ठापित 'समानता' सिद्धांत से संबंधित अनेक निर्णयों का सर्वेक्षण किया और कुछ सिद्धांतों को शामिल किया। सिद्धांत में नं। 3, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यद्यपि वर्गीकरण अनुमेय था और यह न्यायालयों के लिए किसी भी मामले में वर्गीकरण की वैधता

निर्धारित करने के लिए भ्रामक सटीकता पर जोर देने या सैद्धांतिक परीक्षणों को लागू करने के लिए नहीं था, लेकिन साथ ही, वर्गीकरण को केवल तभी उचित माना जाएगा जब यह स्पष्ट रूप से मनमाना न हो। इस बात पर भी जोर दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 14 में रेखांकित उद्देश्य सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए गए विशेषाधिकारों और लगाए गए दायित्वों दोनों में समान रूप से व्यवहार करना था। न्यायालय द्वारा दिया गया जोरदार संदेश निम्नलिखित था:

(4) इसका केवल यह अर्थ है कि समान परिस्थिति वाले सभी व्यक्तियों के साथ प्रदत्त विशेषाधिकारों और अधिरोपित देनदारियों दोनों में समान व्यवहार किया जाएगा। समान कानूनों को एक ही स्थिति में सभी पर लागू करना होगा, और एक व्यक्ति और दूसरे के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए यदि कानून के विषय-वस्तु के संबंध में उनकी स्थिति काफी हद तक समान है।

एक अन्य सिद्धांत जिसे दोहराया गया था कि वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत होना चाहिए, अर्थात्, यह केवल कुछ गुणों या विशेषताओं पर आधारित नहीं होना चाहिए जो एक साथ समूहबद्ध सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं

और अन्य लोगों में नहीं जो छूट गए हैं, लेकिन उन गुणों और विशेषताओं का कानून के उद्देश्य के साथ उचित संबंध होना चाहिए।

10. अनुच्छेद 14 किसी भी रूप में मनमानेपन से बचाता है। इस सिद्धांत को E.P. में स्पष्ट रूप से समझाया गया था। रोयप्पा बनाम स्टेट ऑफ T.N. [E.P.] रोयप्पा बनाम राज्य T.N. का मानना है कि मूल सिद्धांत जो अनुच्छेद 14 और 15 दोनों को सूचित करता है वह समानता और भेदभाव के खिलाफ निषेध है। हम उस निर्णय के निम्नलिखित अंश को भी उद्धृत करना चाहेंगे, जो इस प्रकार है:

सकारात्मक दृष्टिकोण से, समानता मनमानेपन के विरोधी है। वास्तव में, समानता और मनमानेपन कट्टर दुश्मन हैं; एक गणराज्य में कानून के शासन से संबंधित है जबकि दूसरा, एक पूर्ण सम्राट की सनक और सनक से संबंधित है। जहां कोई कार्य मनमाना है, उसमें यह निहित है कि यह राजनीतिक तर्क और संवैधानिक कानून दोनों के अनुसार असमान है और इसलिए, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और यदि यह सार्वजनिक रोजगार से संबंधित

किसी भी मामले को प्रभावित करता है, तो यह अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है। अनुच्छेद 14 और 16 राज्य की कार्रवाई में मनमानेपन पर प्रहार करते हैं और निष्पक्षता और व्यवहार की समानता सुनिश्चित करते हैं।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि स्पष्टीकरण प्रकृति में अत्यधिक भेदभावपूर्ण है।

11. इस मामले को दूसरे कोण से भी देखा जा सकता है, जिसके समान परिणाम मिलेंगे।
12. हमें यह ध्यान रखना होगा कि अधिसूचना दिनांक 4-5-1999 को देखें, यह उपरोक्त कच्चे माल पर प्रवेश कर की दर है जिसे घटाकर 1% कर दिया गया है। इसका प्रभाव यह होगा कि कोई भी व्यक्ति कच्चा माल लाता है। मध्य प्रदेश राज्य के भीतर कोयला, जिप्सम और बॉक्साइट पर केवल 1% का प्रवेश कर देय था। एक बार इस पहलू को ध्यान में रखने के बाद, इसका कानूनी प्रभाव यह होना चाहिए कि अपीलार्थियों सहित सभी व्यक्ति, जिन्होंने पहले ही कर का भुगतान कर दिया था, उन्हें

केवल 1% की दर से कर का भुगतान करना था। इसलिए, यदि उन्होंने अधिक दर पर कर का भुगतान किया था, तो वे भुगतान की गई कर की अतिरिक्त राशि की वापसी के हकदार थे। राज्य द्वारा उच्च न्यायालय में या इस न्यायालय में या किसी अन्य रूप में दायर जवाबी-हलफनामे में कोई कारण सामने नहीं आ रहा है कि विक्रेता द्वारा 1% से अधिक भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को वापस नहीं करने के लिए इस तरह के स्पष्टीकरण को जोड़ने की आवश्यकता क्यों थी, जो इस अवधि के लिए कानूनी रूप से देय प्रवेश कर था। एक बार जब हम इस कोण से मामले पर विचार करते हैं, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि देय प्रवेश कर केवल 1% था, इसलिए किसी भी व्यक्ति को उच्च दर पर भुगतान करने के लिए कहना संविधान के अनुच्छेद 265 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होगा।

13. संविधान के अनुच्छेद 265 को दिए गए संदर्भ में अनुच्छेद 14 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। दोनों प्रावधानों के बीच इस सह-संबंध को कुन्नथट थथुन्नी मूपिल नायर बनाम केरल राज्य में खूबसूरती से सामने लाया गया है। [कुन्नतात थथुन्नी मूपिल नायर बनाम केरल राज्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 552: (1961) 3 एस. सी. आर. 77] (AIR pp. 557-58, para 7)

"7. केरल राज्य द्वारा अपनाए गए रुख को देखते हुए इन मामलों में विचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 265 अधिनियम की संवैधानिकता के खिलाफ हमले का पूर्ण उत्तर है। इसलिए, उस लेख के दायरे और प्रभाव पर विचार करना आवश्यक है। अनुच्छेद 265 राज्य की कर लगाने की शक्ति पर एक सीमा अधिरोपित करता है क्योंकि यह उपबंध करता है कि राज्य विधि के प्राधिकार के सिवाय कोई कर नहीं लगाएगा या एकत्र नहीं करेगा, अर्थात् कोई कर केवल कार्यकारी आदेश द्वारा नहीं लगाया जा सकता है या एकत्र नहीं किया जा सकता है। यह कानून के अधिकार से किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ वैध कानून होना चाहिए। कानून के वैध होने के लिए प्रस्तावित कर विधायी विधायिका की विधायी क्षमता के भीतर होना चाहिए जो कर अधिरोपित करता है और उसके संग्रह को प्राधिकृत करता है और दूसरा, कर संविधान के अनुच्छेद 13 में निर्धारित शर्तों के अधीन होना चाहिए। अनुच्छेद 13 (2) द्वारा परिकल्पित ऐसी शर्तों में से एक यह है कि विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो

अनुच्छेद 14 में समानता के खंड को हटा देता है या कम करता है, जो राज्य को किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या देश के कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करने का आदेश देता है। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि यदि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो इसे असंवैधानिक के रूप में निरस्त किया जाना चाहिए। इन मामलों के प्रयोजन के लिए, हम यह मान लेंगे कि राज्य विधानमंडल के पास कानून बनाने के लिए आवश्यक क्षमता थी, हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इस तरह की क्षमता को गंभीरता से चुनौती दी है। कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी का विस्तार कर लगाने वाले कानूनों तक भी होना चाहिए। इसका अन्यथा प्रतिवाद नहीं किया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति पर समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि एक ही प्रकार की संपत्ति पर कर लगाया जाना है, तो कराधान एक ही मानक से होना चाहिए, ताकि कराधान का बोझ उस प्रकार और संपत्ति की सीमा रखने वाले सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़ सके। यदि सामान्यतः कराधान, कराधान के समान आधार पर, उस

विशेष प्रकार और संपत्ति की सीमा के संदर्भ में सभी पर समान भार अधिरोपित करता है, तो कानून असमानता के आधार पर हमला करने के लिए खुला नहीं होगा, भले ही कराधान का परिणाम यह हो कि विभिन्न व्यक्तियों पर कुल भार असमान हो सकता है। इसलिए, यदि विधायिका ने व्यक्तियों या संपत्तियों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जो आय या संपत्ति के संदर्भ में कराधान की विभिन्न दरों के अधीन हैं, तो ऐसा वर्गीकरण इस आधार पर असमानता के हमले के लिए खुला नहीं होगा कि इस तरह के वर्गीकरण से उत्पन्न कुल बोझ असमान है। इसी तरह, विभिन्न प्रकार की संपत्ति पर कर की अलग-अलग दरें लागू की जा सकती हैं, लेकिन जब तक वर्गीकरण के लिए एक तर्कसंगत आधार है, अनुच्छेद 14 इस तरह के वर्गीकरण के रास्ते में नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न वर्गों की संपत्तियों पर असमान बोझ पड़ेगा। लेकिन यदि समान रूप से स्थित संपत्ति का एक ही वर्ग कराधान की घटनाओं के अधीन है, जिसके परिणामस्वरूप असमानता होती है, तो कानून को समान प्रकार की संपत्ति के धारकों के बीच असमानता पैदा करने के रूप में निरस्त किया जा सकता है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित

किया जाना चाहिए कि एक कराधान क़ानून इस आधार पर हमले से पूरी तरह से अछूता नहीं है कि यह अनुच्छेद 14 में समानता खंड का उल्लंघन करता है, हालांकि अदालतें एक कराधान क़ानून में अंतर्निहित नीति से संबंधित नहीं हैं या क्या एक विशेष कर को अलग तरीके से या इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता था कि अदालत अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत सोचे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 के आधार पर हमले के संदर्भ में अधिनियम की जांच की जानी चाहिए।

14. इस स्तर पर, हम इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे जो कि वर्तमान स्थिति के काफी निकट है, अर्थात्, कॉरपोरेशन बैंक बनाम सरस्वती अभारांसाला [कॉरपोरेशन बैंक बनाम सरस्वती अभारांसाला, (2009) 1 एससीसी 540]। यह वह मामला था जहां बिक्री कर की दर 1% से घटाकर 0.5% कर दी गई थी। 1075/99 दिनांक 27-12-1999, जिसे 1-4-1999 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। उस मामले में प्रतिवादी, जिसने 6-4-1999 से 10-12-1999 की अवधि के लिए बिक्री कर @1% का भुगतान किया था, ने भुगतान किए गए अतिरिक्त कर यानी i.e की वापसी का दावा किया। 0.5%

से अधिक। इस अनुरोध को सहायक आयुक्त, बिक्री कर ने अस्वीकार कर दिया था। निर्धारिती ने सहायक आयुक्त के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। हालांकि, डिवीजन बेंच ने अधिकारियों को एकत्र की गई अतिरिक्त राशि को वापस करने का निर्देश देते हुए निर्धारिती की अंतर-अदालत अपील को स्वीकार कर लिया। डिवीजन बेंच के उक्त निर्णय को इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित करते हुए बरकरार रखा गया था कि धन वापसी न करने से न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड का उल्लंघन होगा, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 265 के अंतर्गत भी होगा जो यह अधिदेश देता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।

15. उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश उद्धृत करने योग्य हैंः  
(कॉरपोरेशन बैंक मामला [ कॉरपोरेशन बैंक बनाम सरस्वती आभारशाला, (2009) 1 एससीसी 540], एससीसी पृष्ठ 545, पैरा 19-22)

"19. भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। अतः उक्त उपबंध के संदर्भ में, कर उपबंध के अधिरोपण से संबंधित सभी अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, जिस बिन्दु पर कर का संग्रहण किया जाना है, कर की दर और उसकी वसूली भी विधि के अनुसार सख्ती से की जानी चाहिए।

20. यदि किसी कानून के मूल प्रावधान में धनवापसी का प्रावधान है, तो राज्य आम तौर पर एक अधीनस्थ कानून द्वारा यह निर्धारित नहीं कर सकता था कि गलती से भी भुगतान किए गए कर को वापस नहीं किया जाएगा। यदि किसी कर का भुगतान निर्दिष्ट कर से अधिक किया गया है, तो 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' के सिद्धांत से जुड़े मामलों को छोड़कर, प्राप्त अतिरिक्त कर को वापस किया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड को ध्यान में रखते हुए यथोचित रूप से कार्य करने के लिए बाध्य है।

21. यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग है क्योंकि यह प्रतिवादी राज्य का मामला नहीं है कि खरीदार ने अपने द्वारा एकत्र की गई कर की अतिरिक्त राशि को खरीदारों को दे दिया है।

22. इस स्वीकार किए गए तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 6-4-1999 और 10-12-1999 की अवधि के लिए कर एकत्र किया गया था और भुगतान किया गया था, जो 1-4-1999 से घटाकर 0.5% कर दिया गया था, राज्य, हमारी राय में, इसके साथ जमा की गई अतिरिक्त राशि को वापस करने के लिए बाध्य है।

16. यह संभव है, जैसा कि राज्य के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया था, कि इस स्पष्टीकरण को जोड़ते समय सरकार ने अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत को ध्यान में रखा था। संभवतः इसी कारण से, उच्च न्यायालय ने इंडियन ऑयल कॉर्प के फैसले का भी उल्लेख किया। [इंडियन ऑयल कॉर्प. v. नगर निगम, जालंधर, (1993) 1 एससीसी 333] हालांकि, केवल इस तरह की धारणा पर, ऊपर उल्लिखित प्रकृति के स्पष्टीकरण को

जोड़ने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष विक्रेता वास्तव में धनवापसी का हकदार है या नहीं, सरकार धनवापसी के लिए उसके आवेदन पर विचार करते समय अन्यायपूर्ण संवर्धन के मुद्दे पर जा सकती है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह नहीं माना जा सकता है कि इन विक्रेताओं द्वारा खरीदारों पर सकारात्मक रूप से बोझ डाला गया था और इसलिए, वे धनवापसी के हकदार नहीं हैं।

17. उपर्युक्त सभी कारणों से हमारी राय है कि दिनांक 4-5-1999 और 5-7-1999 की अधिसूचनाओं में आक्षेपित स्पष्टीकरण असंवैधानिक हैं। हम, तदनुसार, अपील की अनुमति देते हैं और उक्त स्पष्टीकरणों को रद्द करते हैं। कोई खर्च नहीं।

Translated by:  
Pratik Kumar